Statement

Information Regarding the number of Public sector Banks in Rajasthan in which incident of Dacoities/Robberies took place during the years 1985, 1986 and 1987 (upto 31-10-87)

Name of the Bank and branch	Date of occurrence	Amount involved (Rs. in lakhs)	Amount recovered	No. of persons arrested
1985				
1 State Bank of Bikaner and Jaipur ADB Dudu Jaipur.	15-1-85			None
2 UCO Bank Bhagwandas Road Jaipur	25-11-85	1.40	1.40	5
1986				
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
1987				
3 State Bank of India ADB Bhusawar Bharatpur	24-4-87	1.88	1.88	3

राजभाषा अधिनियम का लागू किया जाना

1648 श्री **जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जल संसाधन मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की इस वर्ष कितनी बैठकें हुई और राजभाषा कार्यान्वयन समिति में सभी स्तरों पर गैर-सरकारी सदस्यों को पर्यवेक्षकों के रूप में नामित किए जाने के संबंध में क्या स्थिति है ;

(ख) मंत्रालय, इसके विभागों, संस्थानों और अधीनस्थ कार्यालयों में, हिन्दी अनुभाग को छोड़कर किस-किस अनुभाग में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है तथा यह किस-किस तारीख से किया जा रहा है तथा किन मामलों में हिन्दी को अब तक नहीं अपनाया गया है तथा इसके क्या कारण है , और

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) को मंत्रालय स्तर से निम्नतम स्तर तक पालन न किए जाने के क्या कारण हैं जबकि अधिनियम को पारित हुए 24 वर्ष तथा वार्षिक कार्यक्रम को तैयार किए 10 वर्ष हो चुके है।

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) चालू वर्ष के दौरान मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की एक बैठक हुई है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति में गैर-सरकारी व्यक्तियों को पर्यवेक्षक के रूप में नामित नहीं किया गया है।

(ख) हिन्दी अनुभाग के अतिरिक्त, मंत्रालय के दो अनुभागों, क्रमश. (1) केन्द्रीय रजिस्ट्री तथा (2) सामान्य अनुभाग को राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 8(4) के अन्तर्गत 19-10-87 को विनिर्दिष्ट किया गया है। केन्द्रीय जल आयोग में भगीरथ पत्रिका अनुभाग अपना सम्पूर्ण सरकारी कार्य हिन्दी में करता है।

(ग) मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3 का अनुपालन की जा रही है।

मेघालय में अन्य राज्यों से आये लोगों को परेशान किया जाना

1649. श्री **जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेघालय में अन्य राज्यों से आये लोगों को, जो उस

राज्य मे बहुत वर्षों से वहां रह रहे हैं उस राज्य से चले जाने के लिये बाध्य किया जा रहा है , और

(ख) क्या इस संबध मे विधायको के एक प्रतिनिधि मंडल ने भी प्रधान मत्री से मुलाकात की है; यदि हा, तो सरकार इस संबध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

गृह मत्रालय मे राज्य मत्री (श्री चिन्तमणि पाणिग्रही) (क) खासी पहाड़ी जिलो मे खासी छात्र सघ (के० एस०यू) द्वारा शुरू किये गये आन्दोलन द्वारा हिंसक मोड लेने और गारो पहाड़ी जिलों मे साम्प्रदायिक हिंसा की कुछ घटनाओ के परिणाम स्वरुप बताया जाता है कि कुछ व्यक्तियों ने राज्य छोड़ दिया है ।

(ख) मेघालय के 5 विधायकों का एक प्रतिनिधिमडल 8-10-1987 को प्रधानमंत्री से मिला और उन्हे मेघालय में व्याप्त नवीनतम स्थिति से अवगत कराया । वहा व्याप्त स्थिति का जायजा लेने के लिए गृह राज्य मंत्री और राज्य मंत्री (श्रम) श्रम मंत्रालय ने 13-14 अक्तूबर, 1987 को मेघालय का दौरा किया और तूरा और शिलांग मे जनता के विभिन्न वर्गों से मिले । उन्होने मुख्य मंत्री के साथ स्थिति की समीक्षा की । राज्य सरकार से यह सुनिश्चित करने का विरोध किया गया है कि विस्थापित व्यक्ति अपने निवास और व्यवसाय के स्थानों पर वापस चले जाएं । राज्य सरकार विस्थापित व्यक्तियों की वापसी के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए कदम उठा रही है ।

Raid at the premises of agents of Churhat Lotteries

1650. SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE:

SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Directorate of Revenue Intelligence had raided the New Delhi premises of the agents of Churhat Lotteries of Madhya Pradesh; and

(b) if so, when were the premises raided and what is the progress and findings alongwith the follow-up action in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EXPENDITURE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI B K GADHVI): (a) No, Sir

(b) Does not arise.

Supply of water to farmers in Madhya Pradesh

1651 SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY. Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item which appeared in "The Hindustan Times" dated the 13th October, 1987 wherein it had been stated that there was sufficient water in various dams in Madhya Pradesh but a ban had been put on the supply of water to the farmers, in that state;

(b) if so, what are the reasons therefor; and

(c) whether Government propose to instruct the Madhya Pradesh Government to lift the ban and provide water to the farmers?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES AND THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI RAM NIWAS MIRDHA). (a) to (c) Irrigation projects are operated by State Governments and the release of water for irrigation purposes are regulated by the State authorities in accordance with the priorities decided by them for different uses. This year, owing to severe drought, the total live storage available in the reservoirs towards middle of October 1987 was about 70 per cent of that of last year, and only about half of the design storage. Consequently the State Government has decided to reserve the water for drinking and nistar purposes and release only the balance water for irrigation purposes.